इकाई 10 जनजातीय समस्याएं*

इकाई की रूपरेखा

10.0 परिचय

10.1 प्रवासन

10.1.1 पूर्वोत्तर भारत में पहले जनजातीय प्रवासन

10.1.2 संगठित प्रवासन

10.1.3 प्रवासन के कारण

10.1.4 प्रवासन की प्रकृति और समस्याएं

10.1.5 कोविड-19 राष्ट्रव्यापी तालाबंदी के दौरान प्रवासन/प्रवासियों की समस्याएँ

10.2 शराब की खपत

10.2.1 पारंपरिक पेय पदार्थ

10.2.2 आसुत शराब

10.2.3 केस अध्ययन : शराब की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने और ताड़ी की खपत को नियंत्रित करने के लिए एक आंदोलन

10.3 विकास प्रेरित विस्थापन

10.3.1 विस्थापन में संभावित जोखिम

10.3.2 आदिवासियों में विस्थापन

10.4 पुनःविस्थापन और पुनर्वास

10.4.1 नीतियां और समस्याएं

10.4.2 आदिवासियों के बीच पुनःविस्थापन और पुनर्वास

10.5 भूमि का हस्तांतरण

10.5.1 अर्थ

10.5.2 भूमि हस्तांतरण के रूप

10.5.3 बाहरी ताकतों द्वारा भूमि का अलगाव

10.5.4 गैर-आदिवासियों द्वारा भूमि का हस्तांतरण

10.5.5 गैर-आदिवासियों द्वारा भूमि हस्तांतरण के तरीके

10.5.6 विकास परियोजनाओं द्वारा भूमि का हस्तांतरण

10.5.7 भूमि का आंतरिक हस्तांतरण

10.6 ऋणग्रस्तता और ऋण-बंधन

10.6.1 ऋणग्रस्तता

10.6.2 ऋण-बंधन

10.6.3 संवैधानिक और कानूनी प्रावधान

10.7 स्वास्थ्य

10.7.1 स्वास्थ्य की स्थिति

10.7.2 बीमारियाँ और जनजातीय चिकित्सा प्रणालियाँ

10.7.3 केस अध्ययनः संसाधन की कमी आयुर्वेदिक चिकित्सा के अभ्यास को प्रभावित करती है

*योगदानकर्ताः डॉ. के. कोटेश्वर राव, सहायक प्रोफेसर, मानविकी और सामाजिक विज्ञान विभाग, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, राउरकेला, ओडिशा

10.7.4 आधुनिक स्वास्थ्य देखभाल

10.7.5 केस अध्ययनः जल प्रदूषण के कारण एक आदिवासी गांव में सोलह लोगों की मौत

10.8 रोजगार

10.9 जनजातीय समस्याओं का उनके सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक पहलुओं पर प्रभाव

10.10 सारांश

10.11 संदर्भ

10.12 आपकी प्रगति की जांच करने के लिए उत्तर

अधिगम के उद्देश्य

इस इकाई को पढ़ने के बाद छात्र निम्न बिन्दुओं को समझेंगे :

- जनजातियों द्वारा सामना की जाने वाली विभिन्न समस्याएं जैसे प्रवासन, शराब की खपत, भूमि अलगाव, ऋण-बंधन और ऋणग्रस्तता, विकास-प्रेरित विस्थापन, पुनर्वास और पुनःस्थापना, स्वास्थ्य, रोजगार; तथा
- जनजातीय समस्याओं का उनके सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक पहलुओं पर प्रभाव।

10.0 परिचय

भारत की जनजातियाँ विभिन्न कारणों से अनेक समस्याओं का सामना करती हैं। कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों का मूल कारण आदिवासी क्षेत्रों में ब्रिटिश घुसपैठ और बाद में मैदानी इलाकों से बाहरी लोगों (अधिकारियों, व्यापारियों, आदि) द्वारा जनजातीय क्षेत्रों में घुसपैठ है। वन संसाधनों का दोहन करते हुए, उन्होंने जनजातीय जीवन-पद्धतियों में हस्तक्षेप किया। इस तरह की घुसपैठ, शोषणकारी संपर्क और हस्तक्षेप ने आदिवासी क्षेत्रों में गड़बड़ी पैदा की (कोटेश्वर राव, 2018।)। संस्कृति संपर्क (शोषणकारी) को अधिकांश जनजातीय समस्याओं के उभरने का एक महत्वपूर्ण कारण माना जाता है। चूंकि जनजातियां परंपरागत रूप से आजीविका और जीवन के लिए अपने पर्यावरण पर निर्भर हैं इसलिए उनके सामाजिक-आर्थिक हाशिए पर जाने की ज़्यादा संभावना है।

भारत में जनजातियों और किसानों की कुछ समस्याओं पर इकाई 5, जनजातीय समस्याओं, BANC-105, में चर्चा की गई है (कोटेश्वर राव 2021)। वर्तमान इकाई जनजातीय लोगों के सामने आने वाली कुछ अन्य समस्याओं की समझ को प्रदान करती है। यह पहले/उपरोक्त इकाई में चर्चा की गई कुछ समस्याओं के लिए नए आयाम या संक्षिप्त चर्चा भी प्रस्तुत करता है।

10.1 प्रवासन

प्रवासन (या श्रम प्रवासन) आज आदिवासियों द्वारा सामना की जाने वाली एक व्यापक समस्या है। कोविड-19की पहली लहर और देशव्यापी तालाबंदी (लॉकडाउन) के दौरान समस्या की गंभीरता और भयावहता अधिक स्पष्ट है। आदिवासियों के बीच प्रवासन कोई बहुत पुरानी समस्या नहीं है जो परंपरागत रूप से जंगलों और अपने आवास में उपलब्ध कुछ अन्य प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर हैं। चूंकि पारंपरिक जनजातीय

10.1.1 पूर्वोत्तर भारत में पहले जनजातीय प्रवासन

हालाँकि झारखंड (बिहार), छत्तीसगढ़ (मध्य प्रदेश), उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश के आदिवासी क्षेत्रों से औपनिवेशिक या पूर्व-स्वतंत्रता अवधि के दौरान कुछ प्रवासन पहले हुआ था। उन जनजातियों में उरांव, संथाल, मुंडा और हो शामिल हैं। वे चाय बागानों/सम्पदाओं में काम करने के लिए पूर्वोत्तर भारत विशेष रूप से असम और उत्तरी बंगाल में चले गए। झारखंड और छत्तीसगढ़ की कुछ जनजातियां भी अकुशल रोजगार की तलाश में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में प्रवासन कर चुकी हैं (हसनैन 2019: 254-55; विद्यार्थी और राय 1985)।

स्वतंत्रता के बाद की अवधि में, इन प्रवासित जनजातियों को असम (झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश से) चाय और पूर्व-चाय बागान जनजातियों के रूप में जाना जाता है और लोकप्रिय रूप से "चाय जनजाति" के रूप में जाना जाता है (असम सरकार 2021)। वे लगभग 60 लाख हैं, जिसमें राज्य की कुल आबादी का लगभग 20: है (हसनैन 2019)। इन चाय जनजातियों को असम में अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता नहीं है क्योंकि वे राज्य के लिए स्वदेशी नहीं हैं। वे अभाव, दमन, शोषण और पहचान संकट की भावना का अनुभव करते हैं (शर्मा 2018)।

10.1.2 संगठित प्रवासन

एक संगठित प्रवासन जहां ठेकेदार और बिचौलिए शामिल हैं, एक नई घटना है। इस तरह के प्रवासन बड़े पैमाने पर बिहार, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल की जनजातियों में होते हैं।

10.1.3 प्रवासन के कारण

जनजातीय लोगों के बीच प्रवासन विभिन्न कारकों के कारण होता है। उन्हें दो व्यापक श्रेणियों के अंतर्गत समझा जा सकता है। ये धक्का (पुश) और खींचने (पुल) वाले कारक हैं।

1) **पुश फैक्टर:** उनमें आर्थिक कमजोरियां, गरीबी, भुखमरी, शोषण (सामाजिक-आर्थिक), बीमारियां, प्राकृतिक आपदाएं (जैसे सूखा, अकाल, महामारी और वैश्विक महामारी), भूमि अधिग्रहण के कारण भूमि का नुकसान और भूमि का अलगाव शामिल हैं। गैर-आदिवासी विस्थापन, भूमि का विखंडन, वर्षा आधारित कृषि और अन्य आजीविका/रोजगार की अनुपस्थिति, और वनों की कटाई और वन संसाधनों तक पहुंच में कमी शामिल है (हसनैन 2019: 254; उच्च स्तरीय समिति 2014)।

2) **पुल फैक्टर** : उनमें आजीविका के अवसर, रोजगार के आकर्षण, बेहतर आय की इच्छा और रहने की स्थिति शामिल हैं (हसनैन 2019: 254) ।

   उपरोक्त कारक आदिवासी लोगों को अपनी भूमि छोड़ने या पलायन करने के लिए मजबूर करते हैं। कभी-कभी दोनों श्रेणियों के कारक एक साथ कार्य करते हैं। चूंकि उपरोक्त सभी में गरीबी प्रमुख कारक है ऐसे प्रवासन को गरीबी प्रेरित प्रवासन कहा जाता है। नतीजतन लोग काम के लिए औद्योगिक क्षेत्रों, कस्बों,

शहरों और अन्य दूर-दराज के स्थानों की ओर पलायन करते हैं (जैसे असम के चाय बागानों) ।

अपनी प्रगति जाँचें

1) प्रवासन के क्या कारण हैं?

.....

.....

.....

.....

.....

10.1.4 प्रवासन की प्रकृति और समस्याएं

यह आदिवासी श्रमिक प्रवासन अनौपचारिक हैं क्योंकि प्रवासियों के पास निश्चित मजदूरी, अनुबंध या सामाजिक सुरक्षा नहीं है। प्रवासन की प्रकृति में या तो अस्थायी (मौसमी या चक्रीय) या स्थायी होते हैं। पहले मुख्य रूप से 'मौसमी प्रवासन' होता था; 'स्थायी प्रवासन' बाद में होने लगा। प्रवासी खेतों, बागानों, ईंट भट्टों, घर के निर्माण, उद्योगों, खदानों, आदि में काम करते हैं। मालिकों/नियोक्ताओं, ठेकेदारों और बिचौलियों से उन्हें कम मजदूरी, अधिक काम के घंटे, काम करने और रहने की स्थिति, विभिन्न प्रकार के शोषण (आर्थिक, यौन, आदि) जैसी कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है (हसनैन 2019: 254-55)। आदिवासी विशेषकर युवा, जो रोजगार के लिए मैदानी, शहरी और औद्योगिक क्षेत्रों में प्रवासन करते हैं, वे अपनी संस्कृति/परंपराओं को त्याग सकते हैं और समय के साथ शहरी संस्कृति को अपना सकते हैं।

10.1.5 कोविड-19 राष्ट्रव्यापी तालाबंदी के दौरान प्रवासन/ प्रवासियां की समस्याएँ

देशव्यापी तालाबंदी के कारण कोविड-19 महामारी से प्रवासन और प्रवासियों की सीमा और समस्याएं स्पष्ट हो गयी हैं। कोविड-19 की पहली लहर के दौरान राष्ट्रीय तालाबंदी ने काम, रोजगार और कमाई के अप्रत्याशित नुकसान के कारण प्रवासियों की आर्थिक कमजोरियों को बढ़ा दिया। इसने न केवल उनकी आजीविका बल्कि मूल रूप से उनके परिवार के सदस्यों के जीवन को भी प्रभावित किया है। ऐसे में हजारों-लाखों प्रवासी अपने गांवों को लौटने को मजबूर हो गए। ऐसे प्रवासी मजदूरों को अपनी वापसी विपरीत/यात्रा/मूल स्थानों की यात्रा (विपरीत प्रवासन) के दौरान विभिन्न समस्याओं और दुखों का सामना करना पड़ा।

कोविड-19 के कारण देशव्यापी तालाबंदी ने प्रवासी श्रमिकों की संख्या और उनके गमनागमन पर आँकड़े की कमी को उजागर किया। इसलिए भारत सरकार ने बाद में राष्ट्रीय प्रवासी सूचना प्रणाली (एनएमआईएस) और आदिवासियों के लिए, विशेष रूप से राष्ट्रीय जनजातीय प्रवासन सहायता द्वार का एक प्रवेश द्वार विकसित किया।

राष्ट्रीय जनजातीय प्रवासन सहायता द्वार (नेशनल ट्राइबल माइग्रेशन सपोर्ट पोर्टल)

राष्ट्रीय जनजातीय प्रवासन सहायता द्वार (पोर्टल) प्रवासी श्रमिकों के संबंध में आँकड़े/सूचना एकत्र करता है। प्रवासन आँकड़े चार खण्ड में होगा। 1) जनसांख्यिकीय रूपरेखा 2) आजीविका, 3) कौशल मानचित्रण, और 4) प्रवासन पद्धिति। इस तरह के आंकड़ें सरकारी अधिकारियों के विभिन्न स्तरों के लिए गांव, ब्लॉक/मंडल, जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से उपलब्ध होंगे।

राष्ट्रीय जनजातीय प्रवासन सहायता द्वार (पोर्टल) का उद्देश्य साक्ष्य-आधारित कार्यक्रमों और नीतियों के लिए प्रवासन पर विश्वसनीय सरकारी आँकड़ों के स्रोतों का प्रबंधन करना है। ऐसा द्वार या आंकड़े निम्नलिखित के लिए अपेक्षित हैः

- "स्थानीय आजीविका को बढ़ावा देना....,
- प्रवासी परिवारों को लक्षित तरीके से समर्थन देने के लिए विशेष कार्यक्रम,
- मौजूदा योजनाओं को अधिक प्रभावी और लाभार्थी के अनुकूल बनाने के लिए उपयुक्त रणनीतियों और नीतिगत निर्णयों का निर्माण, और
- सुरक्षित और उत्पादक प्रवासन के लिए शहरों में जनजातीय और अन्य प्रवासी कामगारों को तत्काल सहायता। "

स्रोत : https://shramshakti.tribal.gov.in/

10.2 शराब की खपत

10.2.1 पारंपरिक पेय पदार्थ

आदिवासियों में शराब के सेवन की आदत व्यापक रूप से प्रचलित है। उनके पारंपरिक पेय स्थानीय रूप से प्राप्य होते हैं या विभिन्न पौधों की सामग्री से तैयार किए जाते हैं और उनमें से अधिकांश मादक नहीं होते हैं। उनके स्फूर्तिदायक प्रभाव और कुछ भोजन/पोषण मूल्य, उदाहरण के लिए, मछली के पूँछ के आकार का पेड़ (*कैरियोटौरेंस*) या खजूर के पेड़ (*बोरासस फ्लैबेलिफेरा*) से ताड़ी (एक प्राकृतिक पेय) होने की सूचना है (कोडिरेकला 2018)। कुछ क्षेत्रों में महुआ (*मधुका लोंगिफोलिया*) के फूलों और धान या बाजरा के चावल की स्थानीय सामग्री से पारंपरिक पेय तैयार किए जाते हैं। धान या बाजरा के चावल के किण्वन द्वारा तैयार पेय व्यापक रूप से प्रचलित है; इसे मध्य प्रदेश और उड़ीसा में *हंडिया* जैसे विभिन्न स्थानीय नामों से जाना जाता है (हसनैन 2019: 237-41)। वाणिज्यिक शराब उत्पादों की तुलना में इस तरह के पेय में शराब की मात्रा कम होती है और यह गैर-विषैला होता है (पांडा एवं अन्य, 2014)। *हंडिया* और *ताड़ी* सहित कुछ पारंपरिक किण्वित पेय में प्रोबायोटिक क्षमता होती है (महेश्वरी एवं अन्य, 2020)। आदिवासी परिवार या समुदाय में इस तरह के पेय को अपने त्योहारों, विवाह, अनुष्ठानों और समारोहों के अवसरों के दौरान जब चाहें तैयार और उपभोग करते है (हसनैन 2019: 237-41)।

फिर भी सभी स्वदेशी या स्थानीय पेय समस्या मुक्त नहीं हैं। गांव/समुदाय में कुछ व्यक्ति या लोग कभी-कभार शराब पीने वालों के बजाय आदतन शराब पीने वाले के रूप में मौजूद हो सकते हैं। कई क्षेत्रों में ताड़ी या हंडिया के किण्वन/तैयारी में विभिन्न योगज (पौधे के हिस्से) का उपयोग किया जाता है। उनमें से कुछ योजक उनकी मात्रा के आधार पर हल्के नशीले होते हैं। इस तरह के योजक से बने किण्वित पेय पुराने और भारी शराब पीने वालों को नशा दे सकते हैं। वे अपने परिवारों,

पड़ोसियों और गांव/समुदाय के लिए समस्यात्मक होते हैं।

हालांकि, पारंपरिक पेय पदार्थों (सांस्कृतिक जरूरतों और पोषण मूल्यों) के लाभों को सामान्य रूप से उनकी समस्याओं को दूर करने या बेअसर करने के लिए माना जाता है।

फिर भी सभी स्वदेशी या स्थानीय पेय समस्या मुक्त नहीं हैं। गांव/समुदाय में कुछ व्यक्ति या लोग कभी-कभार शराब पीने वालों के बजाय आदतन शराब पीने वाले के रूप में मौजूद हो सकते हैं। कई क्षेत्रों में *ताड़ी* या *हंडिया* के किण्वन/तैयारी में विभिन्न योगज (पौधे के हिस्से) का उपयोग किया जाता है। उनमें से कुछ योजक उनकी मात्रा के आधार पर हल्के नशीले होते हैं। इस तरह के योजक से बने किण्वित पेय पुराने और भारी शराब पीने वालों को नशा दे सकते हैं। वे अपने परिवारों, पड़ोसियों और गांव/समुदाय के लिए समस्यात्मक होते हैं।

हालांकि, पारंपरिक पेय पदार्थों (सांस्कृतिक जरूरतों और पोषण मूल्यों) के लाभों को सामान्य रूप से उनकी समस्याओं को दूर करने या बेअसर करने के लिए माना जाता है।

अपनी प्रगति जाँचें

2) जनजातीय क्षेत्रों में मुख्य प्रकार के पारंपरिक पेय कौन से हैं?

.....

.....

.....

.....

.....

10.2.2 आसुत शराब (डिस्टिल्ड लिकर)

हालांकि जनजातियों के पास पारंपरिक रूप से अपने स्थानीय/पारंपरिक पेय हैं जो उनके पसंदीदा हैं दुर्भाग्य से अरक (कठोर शराब/मधसार) को पहले ब्रिटिश सरकार द्वारा बढ़ावा दिया गया था (कोटेश्वर राव, 2018।)। ब्रिटिश और भारतीय सरकारों की आबकारी/आबकारी नीतियों और शराब समर्थक वर्ग का उद्देश्य उनके राजस्व में वृद्धि करना है। इस तरह के विकास ने आदिवासियों को पारंपरिक, स्थानीय, सामाजिक और औपचारिक परिस्थितियों और जरूरतों के बावजूद आसुत शराब पर निर्भर रहने और उपभोग करने के लिए मजबूर किया है। इसलिए, एन.के. बोस अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आयुक्त के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान बोस ने आदिवासी क्षेत्रों में शराब विक्रेताओं को "शोषण के प्रतिनिधि" के रूप में बताया। ढेबर आयोग ने ऐसी आसुत शराब बिक्री को बंद करने की सिफारिश की है (हसनैन, 2019: 237-41)।

फिर भी आदिवासी क्षेत्रों में विभिन्न रूपों में शराब की बिक्री जारी है। देशी शराब की आपूर्ति के अलावा अरक का स्थानीय (अवैध) आसवन भी कुछ क्षेत्रों में कभी-कभी कुछ लोगों द्वारा किया जाता है। शराब की ऐसी बिक्री और खपत आज आदिवासी क्षेत्रों में एक बड़ी समस्या है। वे परिवार और समाज के स्तर पर समस्याएं पैदा करते हैं। इनमें आर्थिक कठिनाइयाँ पारिवारिक जीवन और संबंधों में व्यवधान, शारीरिक/घरेलू

हिंसा, सामाजिक अशांति और अन्य अनकहे दुख शामिल हैं। आदिवासी क्षेत्रों में ज्यादातर बाहरी लोगों के स्वामित्व वाली शराब की दुकानें, विशेष रूप से आदिवासी युवाओं के बीच, कभी-कभी अवांछनीय और अवैध गतिविधियों का कारण बन जाती हैं।

आजकल आदिवासी युवा भी धीरे-धीरे शहरी क्षेत्रों से विदेशी मादक पेय (भारतीय निर्मित विदेशी शराब आईएमएफएल या विदेशी शराब) की ओर आकर्षित हो रहे हैं। ये शायद बाजार के जोखिम/अर्थव्यवस्था, प्रवासन आदि के कारण हैं। वे समस्याओं को बढ़ाते हैं। उदाहरण के लिए एक आदिवासी गांव के बाहरी इलाके में, कुछ साल पहले आईएमएफएल की खाली कांच की बोतलें सड़कों के किनारे फेंक दी गईं। उनमें से कुछ टूट गए थे और स्थानीय ग्रामीणों और राहगीरों, विशेष रूप से बच्चों के लिए खतरा पैदा कर रहे थे, जो नंगे पांव स्कूल और आम भूमि क्षेत्रों में जाते थे।

हालांकि अब कई आदिवासी शराब की बुराइयों से वाकिफ हैं। आदिवासी इलाकों में आसुत शराब की बिक्री और खपत के खिलाफ विशेष रूप से आदिवासियों को इससे दूर करने के लिए आंदोलन हुए हैं। उदाहरण के लिए, अगले भाग में निम्नलिखित केस अध्ययन को देखें।

अपनी प्रगति जांचें

3) जनजातीय क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार के मादक पेय क्या हैं?

.....

.....

.....

.....

.....

4) एन.के. बोस ने आदिवासी क्षेत्रों में शराब बेचने वालों को क्या कहा?

.....

.....

.....

.....

.....

10.2.3 केस अध्ययन : शराब की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने और ताड़ी की खपत को नियंत्रित करने के लिए एक आंदोलन

वर्तमान मामला अध्ययन आंध्र प्रदेश में एक विशेष रूप से कमजोर आदिवासी समूह कोंडा रेड्डी पर आधारित है। पूर्वी गोदावरी जिले के अभिकरण क्षेत्र (आईटीडीए, एकीकृत जनजातीय विकास एजेंसी) के एक गाँव के आदिवासी आसुत शराब की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने और आसुत शराब और ताड़ी (पारंपरिक पेय) की खपत को नियंत्रित करने में सफल रहे हैं।

"इस गांव के लोग, मुख्य रूप से महिलाएं, जिनमें से अधिकांश गांव के स्वयं सहायता समूहों की सदस्य थीं, एक साथ शामिल हुईं और इस प्रयास में सक्रिय रूप से भाग

लिया। बेशक वे एक भी प्रयास में आसानी से सफल नहीं हुए। उनका संघर्ष 10 साल पहले शुरू हुआ था, जब इलाके और गांव में भी शराब का आसवन और बिक्री बड़े पैमाने पर हुई थी। वे इस खतरे को रोकने के लिए दृढ़ थे क्योंकि उन्हें अपने शराबी पतियों के साथ कुछ बुरे अनुभव हुए थे। उन्होंने गाँव के चारों ओर जंगल में शराब बनाने के स्थानों की खोज की, सभी शराब को नष्ट कर दिया और शराब बनाने के लिए उपयोग किए जाने वाले सभी बर्तनों और अन्य पात्रों को तोड़ दिया। इसके बाद शराब निर्माताओं को इस तरह की गतिविधि में शामिल नहीं होने की चेतावनी भी दी गई। ग्रामीणों ने शराब के सेवन पर भी नियंत्रण कर लिया। इस गांव में किसी को भी शराब ले जाने की इजाजत नहीं थी। बेशक उन्होंने पीने वालों पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया, अगर वे पीने के लिए दूसरे गांव (गांवों) में गए। हालांकि शराब की चोरी को लेकर ग्रामीण सतर्क थे। इस प्रकार यह धीरे-धीरे शराब की बिक्री और खपत में गिरावट का कारण बना। अगर कोई शराब बेचते पाया जाता है तो उस पर जुर्माना लगाया जाता है। ऐसा ही एक केस अध्ययन दिसंबर 2017का है जब एक परिवार के पास बिक्री के लिए थोड़ी मात्रा में शराब बरामद हुई थी, गांव के राजनीतिक संगठन द्वारा एक सार्वजनिक बैठक में परिवार पर जुर्माना लगाया गया था, जो एक अनौपचारिक संगठन था, जिसमें गांव के सभी वयस्क सदस्य शामिल थे।''

"इस गांव में, कुछ परिवार मुख्य रूप से ताड़ी के मौसम के दौरान *जीलुगु* (*कैरियोटौरेंस*) की ताड़ी बेचने में शामिल हैं। उन्हें हर साल सार्वजनिक सभाओं में ग्रामीणों द्वारा तय किए गए अनुसार कुछ राशि का भुगतान करने की भी आवश्यकता होती है। ग्रामीण अपनी बैठक में इस बात पर भी चर्चा करते हैं कि वर्ष के आगामी मौसम के लिए ताड़ी की बिक्री की अनुमति दी जाए या नहीं और ऐसे व्यवसाय के लिए उन दुकानों/घरों से यदि अनुमति दी जाए तो कितना कर वसूल किया जाए । इस प्रकार, ग्रामीण अपने संगठन के माध्यम से शराब और ताड़ी की बिक्री और खपत को नियंत्रित करते हैं। इसे एक उदाहरण के रूप में लेते हुए, पड़ोसी गांवों ने भी हाल के दिनों में और अब तक कुछ हद तक शराब की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है" (कोटेश्वर राव 2018 : 27-28)।

10.3 विकास प्रेरित विस्थापन

आदिवासी क्षेत्रों में विस्थापन एक प्रमुख समस्या है। विभिन्न विकास और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं (सिंचाई, औद्योगिक, खनन, संरक्षण, आदि) ने बड़ी संख्या में आदिवासियों को विस्थापित किया है। इस तरह के विस्थापन को विकास प्रेरित या विकास के कारण विस्थापन के रूप में जाना जाता है।

विकास परियोजनाएं लोगों को अपने/पैतृक घरों, जमीनों और संपत्तियों को बेदखल करने का कारण बनती हैं, और अपने पुश्तैनी/पैतृक घरों, जमीनों और रहने के स्थानों/गांवों को जबरदस्ती छोड़ देती हैं। वे लोगों को उनके नए स्थानों पर प्राकृतिक संसाधनों तक पहुंच खोने, आजीविका के नुकसान और कई अन्य प्रतिकूल प्रभावों का कारण बनते हैं।

विकास प्रेरित विस्थापन को विस्थापन का सबसे महत्वपूर्ण रूप माना जाता है क्योंकि इसकी मजबूर प्रकृति और विस्थापित लोगों की भयावहता है। विस्थापन के इस रूप में राज्य द्वारा किसी भी प्रकार का बल प्रयोग या बल प्रबल होता है इसलिए इसे अनैच्छिक या जबरन विस्थापन भी कहा जाता है। इस तरह के बल का प्रयोग राज्य के सार्वजनिक प्राधिकरणों द्वारा किया जाता है।

10.3.1 विस्थापन में संभावित जोखिम

विस्थापन में विभिन्न संभावित जोखिम हैं। माइकल सेर्निया (1997, 2000, 2003) ऐसे 9 जोखिमों की पहचान करता है। ये इस प्रकार हैं:

1) भूमिहीनता,
2) बेरोजगारी,
3) बेघर होना,
4) हाशिए पर,
5) खाद्य असुरक्षा,
6) सामान्य संपत्ति संसाधनों (और सेवाओं) तक पहुंच का नुकसान,
7) रुग्णता और मृत्यु दर में वृद्धि,
8) समुदाय/सामाजिक विघटन (विघटन), और
9) शैक्षिक नुकसान (कोडिरेकला 2020 में उद्धृत)।

बाद में मुगाह, डाउनिंग और रॉबिन्सन (डाउनिंग 2002; रॉबिन्सन 2003) द्वारा दो और जोखिमों की पहचान की गई।वे निम्न है:

1) सामुदायिक सेवाओं तक पहुंच का नुकसान (जैसे, स्वास्थ्य क्लीनिक और शैक्षिक सुविधाएं जैसी सार्वजनिक सेवाएं), और
2) मानवाधिकारों का उल्लंघन (जैसे अनुचित मुआवजा, मनमानी गिरफ्तारी, आदि) (कोडिरेकला 2020 में उद्धृत)।

अपनी प्रगति जांचें

5) माइकल सेर्निया और अन्य द्वारा विस्थापन में कितने संभावित जोखिमों की पहचान की गई है?

.....

.....

.....

.....

.....

10.3.2 आदिवासियों में विस्थापन

भारत में विभिन्न विकास परियोजनाओं द्वारा विस्थापन की भयावहता से पता चलता है कि विस्थापित और प्रभावित अधिकांश लोग आदिवासी हैं। उच्च स्तरीय समिति (2014) में उद्धृत कुछ रिपोर्टों के अनुसार, 30.7–40.9 प्रतिशत विस्थापित/प्रभावित लोग आदिवासी हैं। आदिवासी विस्थापन का उच्च अनुपात इसलिए है क्योंकि आदिवासी क्षेत्रों में समृद्ध संसाधनों के कारण कई विकास परियोजनाएं स्थापित हैं और आदिवासी मुख्य रूप से कुछ प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर हैं। विस्थापन की समस्याओं को प्रमुख और हाल ही में पूरी हुई सरदार सरोवर परियोजना और चल रही पोलावरम परियोजना से आसानी से समझा जा सकता है। सरदार सरोवर परियोजना और

पोलावरम परियोजना में विस्थापितों में क्रमशः लगभग 58 प्रतिशत और 50 प्रतिशत आदिवासी थे। अगर हम अन्य परियोजनाओं को देखें जैसे उड़ीसा में ऊपरी इंद्रावती परियोजना में 89 प्रतिशत विस्थापित आदिवासी थे। बिहार में कोयल कारो परियोजना में 88 प्रतिशत विस्थापित आदिवासी थे (कोटेश्वर राव, 2021)।

विस्थापन आदिवासियों की मूर्त और अमूर्त संपत्ति, आजीविका और संसाधन आधार से वंचित करता है। यह मनोवैज्ञानिक आघात और सामाजिक और सांस्कृतिक समस्याओं का भी कारण बनता है। इस तरह के बहुआयामी आघात की भरपाई आसानी से नहीं की जा सकती।

10.4 पुनःविस्थापन और पुनर्वास

10.4.1 नीतियां और समस्याएं

विस्थापित लोगों के लिए विकास परियोजनाओं द्वारा पुनः स्थापन और पुनर्वास (आर एंड आर) प्रदान किया जाता है। विस्थापित लोगों को विस्थापन, पुनःस्थापन और पुनर्वास की विभिन्न समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इनमें भूमि, संपत्ति, आजीविका और संसाधनों का अभाव; सामाजिक और सांस्कृतिक परिणाम; और मनोवैज्ञानिक आघात शामिल हैं। ऐसी समस्याएं पहले बहुत अधिक और गंभीर थीं क्योंकिः 2003 तक राष्ट्रीय स्तर पर परियोजना विस्थापित/प्रभावित परिवारों के लिए कोई पुनर्वास और पुनःस्थापन नीति नहीं थी; तथा "भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्वास अधिनियम, 2013 में उचित मुआवजे और पारदर्शिता का अधिकार" केवल 2014 में लागू हुआ (कोटेश्वर राव 2018बी)।

परियोजना विस्थापित या प्रभावित लोगों ने पुनर्वास और पुनःस्थापन नीतियों के अस्तित्व में आने और लागू होने के बाद भी समस्याओं का सामना किया है और अभी भी समस्याओं का सामना कर रहे हैं। विस्थापित परिवार अपने आर्थिक और सामाजिक-सांस्कृतिक आधार और बुनियादी सुविधाओं की बहाली के लिए परिवार के साथ-साथ गांव स्तर पर उचित पुनःस्थापन और पुनर्वास लाभों के हकदार हैं। हालांकि ज्यादातर परियोजनाओं में उनका अक्सर उल्लंघन किया जाता है।

इस तरह के पुनःस्थापन और पुनर्वास समस्याओं के कुछ कारणों में निम्न शामिल हैंः

- संबंधित सरकार या परियोजना अधिकारियों की मनमानी कार्रवाई,
- अस्पष्ट पुनःस्थापन और पुनर्वास नीतियां जो हाल के दिनों तक मौजूद थीं,
- उन पूर्व नीतियों के प्रावधानों और संचालन में समस्याएं,
- पहले की नीतियों और पुनःस्थापन और पुनर्वास पर मौजूदा कानून का अप्रभावी कार्यान्वयन,
- विस्थापित लोगों की शिकायतों के प्रति उदासीनता और उनके विरोध को नकारात्मक दृष्टिकोण से चित्रित करना (कोडिरेकला 2020)।

10.4.2 आदिवासियों के बीच पुनःविस्थापन और पुनर्वास

जनजातीय क्षेत्रों में स्थित अधिकांश परियोजनाओं में आदिवासियों को पुनःस्थापन और पुनर्वास की अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ा और वे अभी भी पीड़ित हैं। विस्थापित आदिवासियों का अनुपात अधिक है लेकिन पुनर्वासित आदिवासियों का

अनुपात कम है (उच्च स्तरीय समिति 2014)। जनजातीय विस्थापन की मात्रा और उनके नुकसान को अक्सर कम करके आंका जाता है और इसका मूल्यांकन नहीं किया जाता है। इसलिए उन्हें अपर्याप्त मुआवजा मिलता है और पुनःस्थापन और पुनर्वास के उपाय भी अपर्याप्त हैं। उन्हें कभी-कभार ही मुआवजे के तौर पर जमीन मुहैया कराई जाती है। यदि भूमि आवंटित की जाती है, तो वे अक्सर अपर्याप्त, अनुपयुक्त या खराब गुणवत्ता वाली होती हैं जो पुनर्वास स्थलों पर अपने घरों से दूर होती हैं। पुनर्वास केंद्रों में अक्सर उनके पास उचित बुनियादी ढांचे की कमी होती है। इनमें सुरक्षित पेयजल, बिजली, सड़कें, स्कूल और स्वास्थ्य सुविधाएं शामिल हैं। वे ईंधन, चारा, वन संसाधनों/उत्पादों जैसे प्राकृतिक संसाधनों तक पहुंच खो देते हैं। उन्हें मेजबान आबादी के साथ नए रिहायसी स्थलों पर मुकाबला करने की समस्याओं का भी सामना करना पड़ता है।

10.5 भूमि का हस्तांतरण

10.5.1 अर्थ

भूमि का हस्तान्तरण (या भूमि का अलगाव) जनजातीय क्षेत्रों में एक पुरानी और बड़ी समस्या है। चूंकि भूमि आदिवासी लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण संसाधन है और एक विपणन योग्य वस्तु भी है, इसलिए भूमि का अलगाव होता है। भूमि हस्तांतरण (या भूमि का हस्तांतरण) का अर्थ है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को स्वामित्व और कब्जे का हस्तांतरण। जनजातियों के संदर्भ में, भूमि अलगाव का अर्थ है आदिवासी लोग अपनी (आदिवासी) भूमि पर स्वामित्व और नियंत्रण खो देते हैं (कोटेश्वर राव, 2021)।

10.5.2 भूमि हस्तांतरण के रूप

भूमि का अलगाव ज्यादातर बाहरी ताकतों द्वारा होता है। विशेष रूप से आदिवासी क्षेत्रों में आदिवासी से गैर-आदिवासी को भूमि का हस्तांतरण बहुत लंबे समय से होता आ रहा है। हालाँकि भूमि हस्तांतरण आदिवासी समुदाय के बाहर और भीतर दोनों जगह होता है। तो सैद्धांतिक रूप से भूमि अलगाव को दो रूपों/प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है। वे निम्न हैं (अ) बाहरी ताकतों द्वारा भूमि का अलगाव, और (ब) भूमि का आंतरिक हस्तांतरण (आदिवासियों द्वारा)।

10.5.3 बाहरी ताकतों द्वारा भूमि का अलगाव

भूमि का अधिकांश अलगाव बाहरी ताकतों द्वारा होता है। इस तरह का अलगाव इस देश की जनजातियों के लिए एक बड़ी समस्या है। यह दो प्रकार का होता है (अ) गैर-आदिवासियों द्वारा भूमि का हस्तांतरण (ब) आदिवासी क्षेत्र में विकास परियोजनाओं द्वारा भूमि का हस्तांतरण।

अपनी प्रगति जाँचें

6) जनजातीय क्षेत्रों में भूमि हस्तांतरण के मुख्य प्रकार क्या हैं?

.....

.....

.....

.....

10.5.4 गैर-आदिवासियों द्वारा भूमि का हस्तांतरण

जब गैर-आदिवासी प्रवासी और बाहरी लोग जनजातीय भूमि पर अतिक्रमण करते हैं, तो वे जनजातीय लोगों को उनकी भूमि से अलग कर देते हैं। इस तरह के अलगाव के कारण जनजातियों का अपनी भूमि पर नियंत्रण खो जाता है। भूमि हस्तांतरण की ऐसी समस्या आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, असम और उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों के आदिवासी क्षेत्रों में मौजूद है (कौल, 1977) ।

जनजातीय भूमि की सुरक्षा के लिए हमारे पास "राज्य अनुसूचित क्षेत्र विनियम" और "किरायेदारी कानून" जैसे संवैधानिक सुरक्षा उपाय और विधायी उपाय हैं। इस तरह के संरक्षण के बावजूद, गैर-आदिवासियों द्वारा "राज्य के उपकरणों की मिलीभगत से" भूमि का हस्तांतरण जारी है (उच्च स्तरीय समिति 2014: 279)।

एक अध्ययन (मिश्रा, 2002) के अनुसार, आदिवासियों से गैर-आदिवासियों को भूमि हस्तांतरण 85.95% और आदिवासियों से आदिवासियों को 14.04 प्रतिशत था। आदिवासी परिवारों के बीच लंबे समय से ऋणग्रस्तता उनकी जमीनों के अलगाव का मुख्य कारण रहा है। अधिकांश आदिवासी (लगभग 85%) आदिवासी भूमि के हस्तांतरण के खिलाफ अपने संवैधानिक अधिकारों और कानूनों से अनजान थे (कोटेश्वर राव, 2021 में उद्धृत)।

10.5.5 गैर-आदिवासियों द्वारा भूमि हस्तांतरण के तरीके

हस्तांतरणियों (गैर-आदिवासियों) द्वारा भूमि के हस्तांतरण के लिए विभिन्न तरीके अपनाए गए हैं। वे निम्नलिखित हैं:

- बिक्री,
- पट्टे पर देना और गिरवी रखना,
- बेनामी हस्तान्तरण,
- अतिक्रमण या जबरन कब्जा,
- वैवाहिक गठबंधन या रखैल,
- जनजातीय परिवारों द्वारा गैर-आदिवासियों को काल्पनिक रूप से गोद लेना,
- कब्जे का मौखिक हस्तांतरण, और
- भूमि अभिलेखों में हेराफेरी ।

10.5.6 विकास परियोजनाओं द्वारा भूमि का हस्तांतरण

उच्च स्तरीय समिति (2014) के अनुसार आदिवासी क्षेत्र में विकास परियोजनाएं आदिवासी भूमि के हस्तांतरण के मुख्य कारणों में से एक हैं। राज्य मुआवजे/पुनर्वास के लिए अनिवार्य "भूमि के लिए भूमि" प्रावधान प्रदान किए बिना "सार्वजनिक उद्देश्य" के नाम पर भूमि का अधिग्रहण करता था। रिपोर्ट में भूमि हस्तांतरण के कुछ अन्य कारणों का भी पता चलता है, जैसे राजस्व अधिकारियों की मिलीभगत कानूनों की गलत व्याख्या अभिलेखों में हेरफेर और भूमि को हस्तांतरित करने की अनुमति और सामुदायिक भूमि के लिए उपयोगकर्ता प्रथाओं का कोई रिकॉर्ड नहीं है जो सर्वेक्षण में सरकारी भूमि के निपटान संचालन रूप में दर्ज हैं (पृष्ठ 255)।

10.5.7 भूमि का आंतरिक हस्तांतरण

कुछ स्थानों/समयों में, भूमि एक आदिवासी जमींदार से दूसरे आदिवासी को हस्तांतरित की जाती है। इसे भूमि का आंतरिक हस्तांतरण कहा जा सकता है। बाहरी ताकतों द्वारा भूमि हस्तांतरण के साथ तुलना करने पर यह भूमि हस्तांतरण का एक मामूली रूप/मुद्दा है। भूमि के इस आंतरिक हस्तांतरण (या बंधक) के परिणामस्वरूप आंतरिक असमानता होती है जो समुदाय के भीतर भूमि अलगाव का एक रूप है (उच्च स्तरीय समिति 2014)।

10.6 ऋणग्रस्तता और ऋण-बंधन

10.6.1 ऋणग्रस्तता

ऋणग्रस्तता जनजातियों की एक पुरानी व्यापक और कठिन समस्या है। ऋणग्रस्तता किसी अन्य पार्टी (साहूकार) को पैसे का भुगतान करने के दायित्व को संदर्भित करती है। आदिवासी विभिन्न जरूरतों और अवसरों जैसे– विवाह, मृत्यु अनुष्ठान, धार्मिक और सामाजिक दायित्व, चिकित्सा उपचार, खेती, मुकदमेबाजी और शिक्षा के लिए साहूकारों से पैसा उधार लेते हैं। उनकी जरूरतें गरीब आदिवासियों को अपनी जमीनों को साहूकारों को अत्यधिक ब्याज दरों पर गिरवी रखकर पैसे उधार लेने के लिए मजबूर करती हैं। वे "साहूकारों के बेईमान और बेईमान तरीकों" के शिकार हो गए (वर्मा 2017: 184, कोटेश्वर राव, 2021 में उद्धृत)। उधार राशि पर तेजी से बढ़ने वाले ब्याज दर पर मिश्रधन की वापसी भुगतान करना मुश्किल होता। ऐसा ऋण एक सतत प्रक्रिया के रूप में पिता से पुत्र तक पोते तक जाता है । इसलिए यह कहा जाता है कि "कर्ज में रहने वाले आदिवासी हमेशा कर्ज में थे" (वर्मा 2017: 184, कोटेश्वर राव, 2021 में उद्धृत)। ऋणग्रस्तता के विभिन्न कारण होते हैं। ऋणग्रस्तता अक्सर ऋण-बंधन या बंधुआ मजदूरी की स्थितियों की ओर ले जाती है।

10.6.2 ऋण-बंधन

ऋण-बंधन को बस बंधुआ मजदूरी के रूप में समझा जाता है। संयुक्त राष्ट्र '1956 के पूरक सम्मेलन के अनुसार ऋण बंधन "अपनी व्यक्तिगत सेवाओं के देनदार द्वारा या ऋण के लिए सुरक्षा के रूप में अपने नियंत्रण में एक व्यक्ति की प्रतिज्ञा से उत्पन्न होने वाली स्थिति या परिस्थिति है, यदि उन सेवाओं का मूल्य यथोचित मूल्यांकन के रूप में ऋण के परिसमापन के लिए लागू नहीं किया जाता है या उन सेवाओं की लंबाई और प्रकृति क्रमशः सीमित और परिभाषित नहीं हैं"।

सक्सेना के अनुसार ऋण बंधन "एक ऐसी प्रणाली है जिसके तहत एक देनदार अपने श्रम या अपने किसी करीबी के श्रम को लेनदार द्वारा उसे दिए गए ऋण पर भुगतान किए जाने वाले ब्याज के बदले गिरवी रखता है। आमतौर पर गिरवीदार या उसके नामांकित व्यक्ति को केवल ऋण के निर्वहन पर जारी किया जाता है" (हसनैन 2019: 310 में उद्धृत)। चूंकि ऐसे बंधुआ मजदूर को बहुत कम या कोई वेतन/पैसा नहीं मिलता है ऋण चुकौती और बंधुआ मजदूरी का अंत जल्द नहीं हो सकता है। व्यक्ति लंबे समय से काम में फंसा हुआ होता है। रिश्ता महीनों सालों और पीढ़ियों तक चल सकता है (हसनैन 2019)। इस प्रकार, ऋणग्रस्तता ऋण-बंधन की ओर ले जाती है और आदिवासियों को अपनी ही भूमि पर साहूकारों का बंधुआ मजदूर बना देती है (वर्मा 2017: 184)।

10.6.3 संवैधानिक और कानूनी प्रावधान

ऋणग्रस्तता और ऋण-बंधन की समस्याओं से संबंधित विभिन्न संवैधानिक प्रावधान और विधान या विनियम हैं। विधानों में विभिन्न राज्यों के साहूकार विनियमन और ऋण राहत विनियमन, और बंधुआ श्रम प्रणाली (उन्मूलन) अधिनियम, 1976 शामिल हैं। हालांकि, उनके प्रभावी कार्यान्वयन में समस्याएं हैं।

10.7 स्वास्थ्य

10.7.1 स्वास्थ्य की स्थिति

जनजातियों की स्वास्थ्य स्थिति बहुत खराब बताई जाती है। कुछ सामान्य स्वास्थ्य समस्याओं में मलेरिया, दस्त, तपेदिक, निमोनिया, सांप और बिच्छू के काटने और फ्लोरोसिस शामिल हैं। उदाहरण के लिए देश के 46% मलेरिया के मामले और 70% फाल्सीपेरम के मामले देश की 8.6% आदिवासी आबादी से आते हैं (अनीता 2018)। दूसरे शब्दों में, उनके खराब स्वास्थ्य की स्थिति का कारण दूर-दराज और अलग-अलग इलाकों में उनका रहना, निरक्षरता, बीमारियों के कारणों की अज्ञानता, गरीबी, सुरक्षित पेयजल की कमी, खराब स्वच्छता, कुपोषण, गरीब जैसे कारकों की परस्पर क्रिया है। मातृ एवं प्रसव पूर्व देखभाल, खराब बाल स्वास्थ्य सेवाएं, टीकाकरण के निम्न स्तर, कम संस्थागत प्रसव, अप्रभावी विकास कार्यक्रम और स्वास्थ्य और पोषण सेवाएं। जनजातियों की खराब स्वास्थ्य स्थिति विभिन्न कारकों से प्रभावित होती है, जिन्हें सांस्कृतिक, आर्थिक, शैक्षिक, भौगोलिक, जनसांख्यिकीय और राजनीतिक कारकों में वर्गीकृत किया जा सकता है। ऐसे कारक बदले में जनजातीय स्वास्थ्य चाहने वाले व्यवहार को प्रभावित करते हैं। सामान्य रूप से आदिवासियों और विशेष रूप से टीबी के लक्षणों वाले लोगों के बीच स्वास्थ्य सेवा चाहने वाले व्यवहार में देरी चिंता का विषय है (अनीता, 2018)।

यह बताया गया है कि आदिवासी आबादी में कैल्शियम, आयरन, विटामिन ए और सी जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी होती है। ऐसी कमियों का कारण आदिवासी आहार से बाजरा का गायब होना है (अनीता, 2018)। जैसे-जैसे वे बाजार आधारित खाद्यान्न, दालों और सब्जियों पर निर्भर होते जा रहे हैं, वे कुछ नई स्वास्थ्य समस्याओं का सामना कर रहे हैं।

10.7.2 बीमारियाँ और जनजातीय चिकित्सा प्रणालियाँ

जनजातियां विभिन्न प्रकार की बीमारियों का अनुभव करती है। जनजातीय बीमारियां उनके विभिन्न विश्वासों, मूल्यों, दृष्टिकोणों और प्रथाओं से प्रभावित और संबोधित हैं। उनमें से कुछ को आधुनिक चिकित्सा द्वारा पहचाना जाता है और कुछ अन्य को केवल उनकी स्थानीय/पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों द्वारा समझाया जाता है, जिन्हें नृजाति चिकित्साविज्ञान के रूप में जाना जाता है।

जैसा कि फोस्टर (1976) वर्णन करते है जनजातीय समाजों में दो प्रकार की चिकित्सा प्रणालियाँ मौजूद हैं। ये व्यक्तिगत और प्राकृतिक चिकित्सा प्रणालियाँ हैं। व्यक्तिगत चिकित्सा प्रणाली में बीमारी/रोग को एक प्रतिनिधि के कारण समझाया गया है – मानव (चुड़ैल या जादूगर), गैर-मानव (भूत, दुष्ट/पूर्वज आत्मा) या अलौकिक (ईश्वर या ऐसा शक्तिशाली प्राणी)। दूसरे शब्दों में कुछ बीमारियों के लिए जादू टोना या टोना-टोटका, भूत-प्रेत, बुरी नजर, किसी देवता/देवता की नाराजगी आदि को

जिम्मेदार ठहराया जाता है। ऐसी बीमारियों का प्रबंधन जादुई-धार्मिक प्रथाओं द्वारा किया जाता है।

प्राकृतिक चिकित्सा प्रणाली में बीमारियां प्राकृतिक परिस्थितियों या ताकतों (उदाहरण के लिए ठंड, गर्मी, शरीर में असंतुलन, रोग पैदा करने वाले रोगाणु) के कारण होती हैं। ऐसी बीमारियों का प्रबंधन आयुर्वेदिक दवाओं द्वारा किया जाता है। एक पारंपरिक चिकित्सक आमतौर पर आयुर्वेदिक दवा और जादू-धार्मिक प्रथाओं दोनों की सेवाएं प्रदान करता है। कुछ गांवों में जड़ी-बूटियों के चिकित्सक भी मौजूद हो सकते हैं। हालांकि, नृवंशविज्ञान संबंधी प्रथाएं विभिन्न कारकों से प्रभावित होती हैं जिनमें आधुनिक चिकित्सा, स्थानीय विशेषज्ञों/ चिकित्सकों की कमी, बदलते परिवेश और वन संसाधनों की कमी और प्रजातियों की कमी शामिल हैं। उदाहरण के लिए, नीचे दिए गए केस अध्ययन को पढ़ें।

10.7.3 केस अध्ययनः संसाधन की कमी आयुर्वेदिक चिकित्सा के अभ्यास को प्रभावित करती है

आंध्र प्रदेश के कोंडा रेड्डी जनजाति के 60 साल के एक बुजुर्ग कहते हैंः

"मैं हड्डी के फ्रैक्चर, मोच और हड्डी से संबंधित कुछ दर्द के इलाज के लिए *चेकमांडू* (आयुर्वेदिक दवा) का विशेषज्ञ हूं। मैं कुछ दिन पहले गिर गया था और पीठ में दर्द हो रहा था। लेकिन मैं अपना इलाज नहीं कर सका, भले ही मुझे प्रभावी इलाज पता हो। क्योंकि, उपचार के लिए *नरामामिडी* (*लिट्सिया डिकैनेंसिस*) पेड़ की छाल की आवश्यकता होती है, और छाल उपलब्ध नहीं होती है क्योंकि गिरिजाना सहकारी निगम (जीसीसी) द्वारा इसकी उच्च मांग और लोगों द्वारा संसाधन के अत्यधिक दोहन के कारण पेड़ नष्ट हो जाते हैं। तो मेरे पास अस्पताल जाने के अलावा और कोई विकल्प नहीं बचा था... इस प्रकार, मुझे अपने स्वयं के प्रभावी उपचार का उपयोग करने के बजाय स्थानीय संसाधनों *नरामिदी* की छाल की कमी के कारण अंग्रेजी दवा के लिए अनावश्यक रूप से कुछ राशि खर्च करनी पड़ी (कोडिरेकला 2015)।

10.7.4 आधुनिक स्वास्थ्य देखभाल

आदिवासी लोग भी पूरक या वैकल्पिक चिकित्सा के रूप में आधुनिक चिकित्सा पद्धतियों पर निर्भर हैं। आधुनिक स्वास्थ्य देखभाल के महत्व को कई कारणों से समझा जा रहा है। इनमें बदलती पारिस्थितिक स्थितियां, नई मान्यताएं और व्यवहार, आदिवासी क्षेत्रों में नई स्वास्थ्य समस्याएं, आधुनिक स्वास्थ्य देखभाल के बारे में जागरूकता बढ़ाना और आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाओं की उपलब्धता और पहुंच शामिल हैं। आदिवासी विशेष रूप से कुछ स्वास्थ्य समस्याओं के लिए आधुनिक चिकित्सा और स्वास्थ्य देखभाल की मांग कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें उनके लिए अन्य प्रभावी उपचार नहीं मिलते हैं।

आधुनिक चिकित्सा की आवश्यकता और बढ़ती निर्भरता के बावजूद, आदिवासियों को विभिन्न कारणों से आधुनिक चिकित्सा और स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं तक कम पहुंच का अनुभव होता है। उनकी समस्याओं को निम्नलिखित मामला अध्ययन से समझा जा सकता है।

10.7.5 केस अध्ययनः जल प्रदूषण के कारण एक आदिवासी गांव में सोलह लोगों की मौत

यह बताया गया था कि 29 मई से 21 जून 2017 तक एक दूरदराज के आदिवासी गांव चपराई में सोलह लोगों की 2-3 सप्ताह में मृत्यु हो गई। इन मौतों के कारणों की अलग-अलग रिपोर्ट की गई। लेकिन जल प्रदूषण और संबंधित प्रकोप को इसका मुख्य कारण माना जा रहा था। मौतों की जानकारी काफी देर से (लगभग 3 हफ्ते बाद, 24 जून 2017 को) गांव से दूर होने के कारण सामने आई। यह गांव आंध्र प्रदेश के पूर्वी गोदावरी जिले में वाई. रामावरममंडल की बोड्डागंडी पंचायत में स्थित है। यह एक मध्यम आकार का (आदिवासी) गांव है। 2011 की जनगणना के अनुसार, गांव में 329 की आबादी वाले कुल 71 परिवार हैं। आंध्र प्रदेश के 67.02% की तुलना में इसकी साक्षरता दर 19.84% है। यह न तो सड़क से या टेलीफोन संचार से जुड़ा था। लोग पीने के लिए पहाड़ी धारा के पानी और स्वास्थ्य के लिए नृवंशविज्ञान पर निर्भर थे। गांव में कोई सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता (सीएचडब्ल्यू) या आशा (मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता) कार्यकर्ता नहीं था। आधुनिक स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं आसानी से उपलब्ध नहीं हैं क्योंकि वे गांव से बहुत दूर स्थित हैं (रेडडेम, 2019)।

उपरोक्त केस अध्ययन पारंपरिक चिकित्सा प्रणाली और आधुनिक स्वास्थ्य देखभाल के बीच की खाई को भी उजागर करता है। इस मामले में पारम्परिक चिकित्सा प्रणाली अप्रभावी और आधुनिक चिकित्सा प्रणाली पहुँच से बाहर थी। इसलिए, आदिवासी क्षेत्रों में उनकी सीमाओं के कारण पारंपरिक और आधुनिक चिकित्सा के बीच एक दुविधा भी मौजूद है।

10.8 रोजगार

आज आदिवासी क्षेत्रों में यह एक उभरती हुई समस्या है। कुछ जनजातियाँ जो परंपरागत रूप से कृषि और कारीगरी पर निर्भर हैं, कृषि और गैर-कृषि ने मजदूरों के आर्थिक जीवन को अपनाया है। ऐसा कार्य जनसंख्या वृद्धि के कारण भूमि पर बढ़ते दबाव, आदिवासी क्षेत्रों में खदानों और उद्योगों के खुलने के अवसर आदि के कारण होता है। उन्हें कृषि में आकस्मिक (दैनिक) आधार पर काम मिलता है। गैर-कृषि कार्य अन्य क्षेत्रों और राज्यों में स्थानीय (निकटवर्ती) या गैर-स्थानीय (दूरस्थ) स्थानों पर उपलब्ध हो सकते हैं। वे वानिकी, चाय बागानों, मिलों, खदानों, खदानों, उद्योगों, निर्माण कार्य (सड़कों, रेलवे पटरियों, कारखानों, पुलों, बांधों, घरों, आदि) में काम करते हैं। औद्योगिक श्रम को अपनाने वाली जनजातियाँ मुख्य रूप से झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल से आती हैं। झारखंड का छोटानागपुर क्षेत्र ऐसे औद्योगिक श्रम के लिए लोकप्रिय है।

कुछ शिक्षित आदिवासी अपनी शैक्षिक योग्यता के आधार पर सरकारी और निजी सेवाओं में कार्यरत हैं। वे विशेष रूप से भील, गोंड, संथाल, मिनस, उरांव, मुंडा और हो जैसी प्रमुख जनजातियों से आते हैं। सरकारी क्षेत्र में आदिवासी रोजगार की स्थिति की प्रवृत्ति को समझने के लिए आदिवासियों की उच्च स्तरीय समिति ने 1978 से 2000 तक के आंकड़ों का विश्लेषण किया है।

उनकी रिपोर्ट से पता चलता है कि सरकारी रोजगार का प्रतिशत आदिवासी (अनुसूचित जनजाति) की आबादी के अनुपात से काफी कम है। देश की कुल जनसंख्या "यह या तो अनुसूचित जनजातियों के लिए प्रदान किए गए आरक्षण के

प्रावधान को लागू न करने या रोजगार के लिए उपयुक्त उम्मीदवारों की अनुपलब्धता या दोनों के कारण हो सकता है" (उच्च स्तरीय समिति 2014: 107)। रिपोर्ट से यह भी पता चलता है कि सरकारी क्षेत्र में लगे जनजातीय लोगों का एक उच्च अनुपात समूह डी सेवाओं (अर्ध-कुशल/अकुशल नौकरियों) के लिए है। दूसरे शब्दों में, अधिकांश नौकरियां सेवा सीढ़ी के निचले पायदान पर हैं।

हालांकि, शिक्षित आदिवासी युवा सार्वजनिक या निजी क्षेत्रों (उद्यमों) में कुशल और वेतनभोगी नौकरी के अवसरों की तलाश में हैं। उनमें से कुछ नए रोजगार लेने के लिए शहरी और औद्योगिक क्षेत्रों की ओर बढ़ रहे हैं। ऐसे कुछ लोगों ने एक बार अपने विचार साझा किए कि स्थानीय आदिवासियों को रोजगार के अवसर पैदा करने और प्रदान करने के लिए स्थानीय, समृद्ध प्राकृतिक संसाधनों के आधार पर आदिवासी क्षेत्रों में कुछ उद्यम स्थापित किए जा सकते हैं। तब उनकी बेरोजगारी या काम के लिए पलायन की समस्या का समाधान होगा।

केंद्र और राज्य सरकारें समय-समय पर कौशल विकास और स्वरोजगार के लिए विभिन्न योजनाओं को लागू कर रही हैं। कृषि/वन आधारित सूक्ष्म/लघु उद्योगों की स्थापना। कई प्रयासों के बावजूद नीतिगत अपेक्षाओं और स्थानीय वास्तविकताओं के बीच अंतर मौजूद है। आदिवासियों को बेरोजगारी की समस्या का सामना करना पड़ता है जो शिक्षा के प्रति युवा पीढ़ी के विचारों को प्रभावित करता है।

10.9 जनजातीय समस्याआं का उनके सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक पहलुओं पर प्रभाव

जनजातीय समस्याओं का उनके सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक पहलुओं पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। उनकी चर्चा नीचे की गई है।

प्रवासनः जनजातीय प्रवासन के कारण जनजातीय संस्कृति/परंपराओं में परिवर्तन, नई/आधुनिक संस्कृति समयोपरि और पहचान की हानि होती है क्योंकि यह असम की चाय-उत्पादन से जुड़ी जनजातियों में विशेष रूप से स्पष्ट है। यह आर्थिक पहलुओं में आदिवासी शोषण और उनके नए कार्यस्थलों पर यौन शोषण की ओर भी ले जाता है। दूर-दराज के आदिवासी वंचित और दमन की भावना का अनुभव करते हैं। उन्हें अपने बच्चों की शिक्षा में विभिन्न समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अधिकांश मामलों में उनके बच्चे स्कूली शिक्षा बंद कर देते हैं। कुछ मामलों में, बच्चों को उनके रिश्तेदारों के साथ उनके मूल स्थानों पर स्कूली शिक्षा के लिए छोड़ दिया जाता है। जो माता-पिता अपने बच्चों को कार्यस्थल पर स्कूल भेजना चाहते हैं उन्हें स्कूल की अनुपलब्धता या दूरी, स्कूली शिक्षा की लागत आदि के कारण भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है।

शराब की खपतः शराब की खपत की समस्या के सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रभाव होते हैं, जो मुख्य रूप से पेय के प्रकार और खपत के स्तर पर निर्भर करता है। पारंपरिक पेय पदार्थों के सेवन का सांस्कृतिक, सामाजिक और धार्मिक महत्व है। ऐसे पेय पदार्थों का सेवन परिवार, नातेदारी समूह या समुदाय में किया जाता है। वे मुख्य रूप से उत्सव और अनुष्ठान के अवसरों जैसे वार्षिक त्योहारों, विवाहों, मृत्यु अनुष्ठानों, यौवन समारोहों और कुछ सामुदायिक समारोहों के दौरान लिए जाते हैं। पारंपरिक पेय पदार्थों में भी स्फूर्तिदायक प्रभाव और कुछ पोषण मूल्य हो सकते है ।

हालांकि, कुछ राजनीतिक और आर्थिक कारकों ने आदिवासियों को अपनी पारंपरिक,

स्थानीय, सामाजिक और औपचारिक परिस्थितियों और जरूरतों के बावजूद आसुत शराब पर निर्भर रहने और उपभोग करने के लिए मजबूर किया है। शराब की बिक्री और खपत, जो या तो बाहर से आपूर्ति की जाती है या कुछ क्षेत्रों में कुछ लोगों द्वारा स्थानीय रूप से आसुत की जाती है, आज आदिवासी क्षेत्रों में एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। वे पारिवारिक संबंधों को बाधित करते हैं, घरेलू हिंसा, आर्थिक तंगी, सामाजिक अशांति और अन्य दुखों का कारण बनते हैं। बाहर से शराब के आपूर्तिकर्ता कुछ अवांछनीय प्रभाव भी पैदा कर सकते हैं, खासकर आदिवासी क्षेत्रों के युवाओं में।

विकास प्रेरित विस्थापनः विकास परियोजनाओं द्वारा विस्थापन लोगों को निम्नलिखित तरीकों से प्रभावित करता हैः अपने/पैतृक घरों, और भूमि और संपत्तियों को बेदखल करना; अपने पुश्तैनी/पैतृक घरों, जमीनों और रहने के स्थानों/गांवों को जबरदस्ती छोड़ना; प्राकृतिक या सामान्य संपत्ति संसाधनों तक पहुंच खोना; नौकरियों, आजीविका और खाद्य सुरक्षा का नुकसान; सामुदायिक या सार्वजनिक सेवाओं जैसे स्वास्थ्य दवाखाना और शैक्षिक सुविधाओं तक पहुंच का नुकसान; सामाजिक विघटन और हाशिए पर; रुग्णता और मृत्यु दर में वृद्धि; अनुचित मुआवजे और मनमानी गिरफ्तारी जैसे मानवाधिकारों के उल्लंघन से पीड़ित; मनोवैज्ञानिक आघात; और नए स्थानों पर विभिन्न अन्य प्रतिकूल प्रभाव (सामाजिक और सांस्कृतिक समस्याएं)।

पुनःस्थापन और पुनर्वासः विस्थापित लोगों को नए स्थानों पर पुनःस्थापन और पुनर्वास की कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इनमें भूमि, संपत्ति, आजीविका और संसाधनों से वंचित करने के विभिन्न रूप; सामाजिक और सांस्कृतिक परिणाम; और कई अन्य प्रतिकूल प्रभाव शामिल हैं। विस्थापित परिवार अपने आर्थिक और सामाजिक-सांस्कृतिक आधार और ढांचागत सुविधाओं को बहाल करने के लिए परिवार और ग्राम स्तर पर उचित पुनःस्थापन और पुनर्वास लाभ पाने के हकदार हैं। हालांकि, अधिकांश परियोजनाओं में उनका बड़े पैमाने पर उल्लंघन किया जाता है।

भूमि का हस्तांतरणः जनजातीय क्षेत्रों में भूमि के अलगाव के कारण आदिवासी लोगों को अपनी भूमि का स्वामित्व और नियंत्रण सहित अपनी भूमि से हाथ धोना पड़ता है।

ऋणग्रस्तता और ऋण-बंधनः आदिवासी साहूकारों के बेईमान और बेईमान तरीकों का शिकार हो जाते हैं। वे ब्याज की जबरन वसूली दरों पर उधार ली गई राशि को एक ऐसी राशि में बदल देते हैं जिसे चुकाना मुश्किल होता है। ऐसा ऋण एक सतत प्रक्रिया के रूप में पिता से पुत्र तक पोते तक जाता रहेगा। तो यह कहा जाता है कि आदिवासी हमेशा कर्ज में डूबे रहते हैं। ऋणग्रस्तता अक्सर ऋण-बंधन या बंधुआ मजदूरी की स्थिति को जन्म देती है जिससे आदिवासी अपनी जमीन पर साहूकारों के बंधुआ मजदूर बन जाते हैं। चूंकि ऐसे बंधुआ मजदूरों को बहुत कम या कोई वेतन/पैसा नहीं मिलता है ऋण चुकौती और बंधुआ मजदूरी को समाप्त करना मुश्किल होता है। व्यक्ति एक विस्तारित अवधि (महीनों, वर्षों और पीढ़ियों) के लिए काम करने में फंस जाता है।

स्वास्थ्यः जनजातियों का स्वास्थ्य सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक और मनोवैज्ञानिक पहलुओं से प्रभावित और प्रभावित होता है। विभिन्न कारकों की परस्पर क्रिया जनजातियों की खराब स्वास्थ्य स्थिति को प्रभावित करती है। इनमें गरीबी, सुरक्षित पेयजल की कमी, खराब स्वच्छता, कुपोषण, खराब मातृ एवं प्रसव पूर्व देखभाल, खराब बाल स्वास्थ्य सेवाएं, टीकाकरण के निम्न स्तर, कम संस्थागत प्रसव, अप्रभावी विकास कार्यक्रम और स्वास्थ्य और पोषण सेवाएं, निरक्षरता के कारणों की

अज्ञानता, बीमारियाँ, और सुदूर और अलग-थलग इलाकों में रहना शामिल हैं। उपरोक्त कारकों को सांस्कृतिक, आर्थिक, शैक्षिक, भौगोलिक, जनसांख्यिकीय और राजनीतिक पहलुओं में वर्गीकृत किया जा सकता है। ऐसे कारक, बदले में, जनजातीय स्वास्थ्य चाहने वाले व्यवहार को प्रभावित करते हैं। जनजातीय स्वास्थ्य की स्थिति उनके सामाजिक-आर्थिक स्तरों को जैसे कि शैक्षिक प्राप्ति, कार्य भागीदारी दर, व्यावसायिक स्थिति और आय/धन भी प्रभावित करती है।

राजगारः आदिवासियों को बेरोजगारी की समस्या का सामना करना पड़ता है, जो उन्हें विभिन्न तरीकों से प्रभावित करता है। शिक्षित आदिवासी युवा अपनी शैक्षिक योग्यता के आधार पर सार्वजनिक या निजी क्षेत्रों में कुशल और सुरक्षित नौकरी के अवसरों की तलाश कर रहे हैं। उनमें से कुछ नए रोजगार लेने के लिए शहरी और औद्योगिक क्षेत्रों की ओर बढ़ रहे हैं। बेरोजगार शिक्षित युवा/व्यस्क पीढ़ी शिक्षा के प्रति युवा पीढ़ी के विचारों को प्रभावित करती है।

उपरोक्त के अलावा औद्योगीकरण, वन नीतियों आदि की कई अन्य समस्याओं ने आदिवासी आबादी को प्रभावित किया है।

10.10 सारांश

भारत की जनजातियों ने कई कारणों से विभिन्न समस्याओं का सामना किया है और अभी भी उनका सामना करना पड़ रहा है। अधिकांश जनजातीय मुद्दों का उद्भव मुख्य रूप से जनजातियों के बाहरी कारकों के कारण होता है। इनमें आदिवासी क्षेत्रों में बाहरी लोगों का प्रवेश और प्राकृतिक संसाधनों (भूमि, जंगल, आदि) का शोषण, "विकास" गतिविधियाँ (बांध, उद्योग, खनन, आदि), प्रतिकूल वन नीतियां आदि शामिल हैं।

प्रवासनः आदिवासी प्रवासन एक व्यापक और गंभीर समस्या है जैसा कि कोविड-19 राष्ट्रव्यापी तालाबंदी के दौरान मजदूरों के विपरीत प्रवासन से स्पष्ट है। प्रवासन के कारणों को दो व्यापक श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है। ये धक्का देने वाले (पुश) और खींचने वाले (पुल) कारक हैं। सभी कारकों में गरीबी प्रमुख है। लोग औद्योगिक क्षेत्रों, कस्बों, शहरों और अन्य दूर-दराज के स्थानों में काम करने के लिए पलायन करते हैं।

शराब की खपतः यह जनजातियों के बीच व्यापक रूप से प्रचलित है। आदिवासी क्षेत्रों में दो प्रकार के पारंपरिक (मादक) पेय हैं। ये हैंः ताड़ी जैसे प्राकृतिक पेय, और हंडिया जैसे किण्वित पेय है ऐसे पेय पदार्थों के प्रभुत्व के अलावा कुछ क्षेत्रों में आसुत शराब मौजूद होता हैं । इन शराबों को दो प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता हैः (अ) देशी शराब/अरक और (ब) भारतीय निर्मित विदेशी शराब। आसुत शराब की बिक्री और खपत आज आदिवासी क्षेत्रों की प्रमुख समस्याओं में से एक है। एन.के. बोस ने आदिवासी क्षेत्रों में शराब विक्रेताओं को "शोषण का प्रतिनिधि" कहा, और ढेबर आयोग ने ऐसी शराब की बिक्री को निलंबित करने की सिफारिश की है।

विकास प्रेरित विस्थापनः विकास परियोजनाएं लोगों को उनके घरों, जमीनों और संपत्तियों को विस्थापित करने और बेदखल करने के लिए मजबूर करती हैं प्राकृतिक संसाधनों तक पहुंच खो देती हैं आजीविका की हानि होती है, और उनके नए स्थानों पर कई अन्य प्रतिकूल प्रभाव पड़ते हैं। यह अपनी मजबूर प्रकृति और विस्थापित लोगों की भयावहता के कारण विस्थापन का सबसे महत्वपूर्ण रूप है। विस्थापन में 11 प्रकार

के संभावित जोखिमों की पहचान की गई है। अधिकांश विस्थापित और प्रभावित लोग आदिवासी हैं, क्योंकि अधिकांश विकास परियोजनाएं आदिवासी क्षेत्रों में स्थित हैं।

पुनःस्थापन और पुनर्वासः विस्थापित लोगों को विभिन्न कारणों से विस्थापन, पुनःस्थापन और पुनर्वास की कई समस्याओं का सामना करना पड़ा और अभी भी उनका सामना करना पड़ रहा है। उनमें निम्न शामिल हैं:

1) विस्थापन एक बहु-आयामी आघात है, जिसे आसानी से मुआवजा नहीं दिया जा सकता है,
2) 2003 तक राष्ट्रीय स्तर पर कोई पुनःस्थापन और पुनर्वास नीति नहीं थी,
3) 2013 तक मौजूद पुनःस्थापन और पुनर्वास नीतियां अस्पष्ट थीं, कुछ प्रावधानों और उनके संचालन में समस्याग्रस्त,
4) पूर्व नीतियों के अप्रभावी कार्यान्वयन और पुनःस्थापन और पुनर्वास के मौजूदा कानून,
5) संबंधित सरकार या परियोजना अधिकारियों की मनमानी कार्रवाई,
6) विस्थापित लोगों की शिकायतों के प्रति उदासीनता और उनके विरोध को नकारात्मक नजरिए से पेश किया जा रहा है।

भूमि का अलगावः आदिवासी क्षेत्रों में यह एक पुरानी, बड़ी और लम्बे समय से चली आ रही समस्या है। यह मुख्य रूप से बाहरी कारकों के कारण होता है जो दो प्रकार के होते हैं: गैर-आदिवासी और आदिवासी क्षेत्रों में विकास परियोजनाएं। गैर-आदिवासियों द्वारा भूमि का अलगाव तब होता है जब बाहरी और गैर-आदिवासी आदिवासी भूमि पर अतिक्रमण करते हैं। ऐसी समस्याएं कई क्षेत्रों/राज्यों में हुई हैं।

ऋणग्रस्तता और ऋण-बंधनः ऋणग्रस्तता उन साहूकारों को धन का भुगतान करने का दायित्व है जिनसे आदिवासी धन उधार लेते हैं। यह जनजातियों की एक पुरानी, व्यापक और कठिन समस्या है। ऋणग्रस्तता के विभिन्न कारणों से आदिवासी साहूकारों के बेईमान और बेईमान तरीकों का शिकार हो जाते है । ऋणग्रस्तता ऋण-बंधन या बंधुआ मजदूरी की ओर ले जाती है। कर्ज-बंधन ने आदिवासियों को अपनी ही जमीन पर साहूकारों का बंधुआ मजदूर बना दिया।

स्वास्थ्यः जनजातियों का स्वास्थ्य विभिन्न सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक, भौगोलिक और शैक्षिक कारकों से प्रभावित होता है। ऐसे कारक बदले में, जनजातीय स्वास्थ्य चाहने वाले व्यवहार को प्रभावित करते हैं। जनजातीय स्वास्थ्य स्थिति उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थिति को भी प्रभावित या प्रतिबिंबित करती है।

रोजगारः आदिवासियों को बेरोजगारी की समस्या का सामना करना पड़ता है, जो उन्हें विभिन्न तरीकों से प्रभावित करता है। इनमें पलायन और शिक्षा के प्रति युवा पीढ़ी के विचार शामिल हैं।

10.11 संदर्भ

Anitha, C.T. (2018). Health status of tribals: An overview of disease burden in tribal areas. In B.V., Sharma, N., Sudhakar Rao, - K., Koteswara Rao (Eds.). *Source book for functionaries in tribal areas*, Volume 4: Health and women and child welfare (Unit 1, pp. 1–9). Hyderabad: Centre for

Innovations in Public Systems.

Foster, G.M. (1976). *Disease etiologies in non-western medical systems*. American Anthropologist, 78(4), 773–782

Government of Assam. (2021). *Tea tribes welfare* (Directorate for welfare of tea and ex-tea garden tribes). Retrieved from https://ttwd.assam.gov.in/about-us/our-history Hasnain, N. (2019). Tribal India (7th ed.). Delhi: Palaka Prakashan.

High Level Committee.(2014). Report of the high level committee on socio-economic, health and educational status of tribal communities of India. Ministry of Tribal Affairs, Government of India.

Kaul, S.K. (1977). A national picture. In S.N., Dubey - R., Murdia (Eds.). *Land alienation and restoration in tribal communities in India* (pp. 185–192). New Delhi: Himalaya Publishing House.

Koteswara Rao, K. (2015). *External intervention, local environment, and knowledge erosion: A forest-based community of South India*. Culture, Agriculture, Food and Environment 37(2), 104–109

(2018). *Cultural adaptation to climate change among indigenous people of South India*. Climatic Change,147(1–2), 299–310

(2020). *Structural violations in resettlement and rehabilitation: Evidence from the Gundlakamma project in Andhra Pradesh*, India. Journal of Asian and African Studies, Vol. 55, issue 4, pp. 552–567

(2018a). Tribal areas: Pre and post-independence. In B.V., Sharma, N., Sudhakar Rao, - K., Koteswara Rao (Eds.). *Source Book for Functionaries in Tribal Areas*, Volume 2: Land and Identity Issues in Tribal Areas (Unit 1, pp. 1–31). Hyderabad: Centre for Innovations in Public Systems.

(2018b). Resettlement and rehabilitation policy and its implementation.In B.V., Sharma, N., Sudhakar Rao, - K., Koteswara Rao (Eds.). *Source Book for Functionaries in Tribal Areas: Volume 2 Land and Identity Issues in Tribal Areas* (Unit 6, pp. 82–116). Hyderabad: Centre for Innovations in Public Systems.

(2021). *Tribal Problems* (Unit 5). Tribes and Peasants in India (BANC-105, pp. 65–82.).Indira Gandhi National Open University (IGNOU), New Delhi.

Maheshwari, M., Gupta, A., - Gaur, S. (2020). *Probiotic potential of traditional Indian fermented drinks*. Current Nutrition - Food Science. 16(5), 638–643

Panda, S.K., Bastia, A.K., - Sahoo, G. (2014). *Process characteristics and nutritional evaluation of handia- A cereal based ethnic fermented food from Odisha*. Indian Journal of Traditional Knowledge,13(1): 149–156

Reddem, A. (2019 April 10). Health, transport and telecom a far cry in

Chaparai. The Hindu. Retrieved from https://www.thehindu.com/news/national/andhra-pradesh/health-transport-and-telecom-a-far-cry-in-chaparai/article26789062.ece

Sharma, I. (2018). *Tea tribes of Assam– Identity politics and search for liberation*. Economic and Political Weekly, 53(9), 74–78

Verma, R.C. (2017). *Exploitation of tribals by money-lenders.Indian tribes through the ages*. Publications Division, Ministry of Information and Broadcasting, Government of India.

Vidyarthi, L.P., - Rai, B.K. (1985, 1976). *The tribal culture of India*. New Delhi: Concept Publishing Company.

10.10 आपकी प्रगति की जांच करने के लिए उत्तर

1) प्रवासन के कारणों को दो व्यापक श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है। ये धक्का देने वाले (पुश) और खींचने वाले (पुल) कारक हैं। खंड 10.1.3 का संदर्भ लें।

2) जनजातीय क्षेत्रों में दो मुख्य प्रकार के पारंपरिक पेय हैं। वे ताड़ी जैसे प्राकृतिक पेय और हंडिया जैसे किण्वित पेय हैं। खंड 10.2.1 का संदर्भ लें।

3) वे पारंपरिक पेय पदार्थ और आसुत शराब हैं। पारंपरिक पेय मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैंः अ) प्राकृतिक पेय, और ब) किण्वित पेय। आसुत शराब मुख्य रूप से दो प्रकार की होती हैः क) अरक या देशी शराब, और ख) भारतीय निर्मित विदेशी शराब। अधिक विवरण हेतु खंड 10.2 का संदर्भ लें।

4) शोषण के प्रतिनिधि अधिक विवरण हेतु खंड 10.2.2 का संदर्भ लें।

5) माइकल सेर्निया और अन्य द्वारा विस्थापन में 11 संभावित जोखिमों की पहचान की गई है। उप-अनुभाग 10.3.1 का संदर्भ लें।

6) दो मुख्य प्रकार हैंः 1) गैर-आदिवासियों द्वारा भूमि का हस्तांतरण, 2) जनजातीय क्षेत्र में विकास परियोजनाओं द्वारा भूमि का अलगाव । खंड 10.5 का संदर्भ लें।